

# असाधारग EXTRAORDINARY

भाग II—सण्ड 3—उप-सण्ड (il) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148]

नई बिल्ली, सोमधार, मार्च 28, 1983/चैत्र 7, 1905

No. 148]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 1983/CHAITRA 7, 1905

इस भाग भें भिन्स पुष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के इत्य में रखा का सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## उद्योग मंत्रालय

(ग्रौद्योगिक विकास विमाग)

### श्रादेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1983

का॰ प्रा॰ 233(प्र)/18क क/प्राई डी मार ए/82:— भारत मरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं॰ का॰ आ॰ 319 (अ)/18एए/आईडीआरए/76, तारीख 27 अप्रैल, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके परचात् उक्त आदेश कहा गया है), केन्द्रीय सरकार ने मैससे प्लाईबोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पाम्पीर, जम्मू-कप्मीर नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध पांच वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात, 26 अप्रेल, 1981 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, यहण करने के लिए जम्मू एण्ड कम्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्राधिकृत किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि लोक हित में यह समीचीत है कि उक्त आदेश पूर्वीक्त पांच वर्ष की अवधि की समाध्यि के पश्चाह भी बना रहे, 31 मार्च. 1517 GI/82 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलत है, और अविध के लिए ऐसे बने रहने के लिए समय-समय पर निवेश जारी किए थे विखिए भारत सरकार के उद्योग मंद्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश कं का आं अा 318 (अ)/18कक/ओ० वि०वि०अ०/81, तारीख 25 अप्रैल, 1981, का ०आ० 287 (अ)/18कक/आईडीआर/ए० तारीख 26 अप्रैल, 1982 भीर का ०आ० 763(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/82. तारीख 25 अक्तूबर, 1982;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोत हित में यह समीचीन है कि उकत आदेश 30 सितम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्भिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे;

. अतः, अब, केम्ब्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951(1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पित धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रवस्त मित्रयों का प्रयोग करने हए, यह निदेश वेती है कि उक्त आवेश 30 सितम्बर,

1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा॰सं॰ 2(6)/81-सीयूएस] ए॰पी॰ सरवन, संयुक्त मनिव

### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)
ORDER

New Delhi, the 28th March, 1983

S.O. 233(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 319(E)/18AA/IDRA/76, dated the 27th April, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Jammu and Kashmir Industries Limited to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Plyboard Industries Limited, Pampore, Jammu and Kashmir, for a period of five years, that is, upto and inclusive of the 26th April, 1981;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1963 [vide Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 318(E)/18AA/IDRA/81, dated the 25th April, 1981, S.O. 287(E)/18AA/IDRA/82, dated the 25th October, 1982].

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a turther period upto and inclusive of the 30th September, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the provise to sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1983.

[File No. 2(6)/81-CUS] A. P. SARWAN, Jt. Secy.